विजेंद्र सिंह

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील सं. 1448/2010)

04 जनवरी, 2017

(दीपक मिश्रा और आर. एफ. नरीमन, न्यायाधिपतिगण]

दंड संहिता 1860: धाराये 302 सपठित धारा 34 – हत्या - सामान्य इरादा - अभियुक्त और उसके परिवार और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बीच दुश्मनी - उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, पीडब्लू 1 के भतीजे की उसके ट्यूबवेल पर हत्या - पीडब्लू 2 एनएस और पीडब्लू 3 ने ट्यूबवेल के शेड के अंदर से बंदूक चलने की आवाज सुनी - घटना स्थल पर पहुंचने पर, उन्होंने अपीलकर्ता आरोपियों को अन्य लोगों के साथ, हथियारों से लैस होकर शेड से बाहर आते देखा - इसके बाद, आरोपी भाग गए - पीडब्लू 1 द्वारा एफआईआर दर्ज की गई - चिकित्सा साक्ष्य से पता चला कि मृतक की मौत बंदूक की गोली से हुई थी - दोषसिद्धि अंतर्गत धारा 302/34 और अधीनस्थ अदालतों द्वारा आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई - उसके बाद दो आरोपियों की मौत - अपील पर, अभिनिर्धारित: साक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आरोपी व्यक्ति हथियारों से लैस होकर शेड में मौजूद थे, उन्हें जाते हुए देखा गया था और मृतक खून से लथपथ पाया गया था - अभियुक्त-अपीलकर्ता अन्य अभियुक्तों के साथ आए थे जो बंदूक से लैस थे और वे स्वयं क्रमशः लाठी और बल्लम लिए हुए थे - हथियार ले जाना, एक विशेष स्थान पर आगमन और एक ही समय में शेड में प्रवेश करना और मृतक की हत्या के धारा 34 के तहत रचनात्मक दायित्व बनता है - घाव के आसपास कोई कालापन या झुलसा नहीं होने से यह विश्वास नहीं होगा कि चोट बंदूक से चली गोली से नहीं लगी है - इसके अलावा,

घटना के बारे में पीडब्लूएस 1-3 की गवाही को बदनाम नहीं किया जा सकता है - वे जांच और सावधानी की कसौटी पर खरे उतरते हैं - कुछ गवाहों की गैर-परीक्षा अभियोजन मामले को प्रभावित नहीं करेगी - इस प्रकार, अपीलकर्ता एम के संबंध में नीचे की अदालतों द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा गया है - जहां तक अपीलकर्ता वी का संबंध है, वह अधिकतम अवधि से अधिक समय तक हिरासत में रहने के कारण रिहा हो गया है - किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 – धाराये 7-ए, 20(संशोधित) - किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007।

धारा 34 - सामान्य आशय – धारा34 की प्रयोज्यता – अभिनिर्धारित: धारा 34 की प्रयोज्यता तथ्य का प्रश्न है और इसे रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य से सुनिश्चित किया जाना है - सामान्य इरादे की कल्पना तुरंत या अपराध के समय की जा सकती है और यह तथ्यों पर निर्धारित होता है।

सबूत - मेडिकल साक्ष्य कि बंदूक की गोली से लगी चोट के लिए पिस्तौल को जिम्मेदार ठहराया गया है - हालांकि, बंदूक की गोली के घाव के आसपास कोई कालापन या झुलसा नहीं है - अभियोजन पक्ष की विश्वसनीयता - माना गया: डॉक्टर ने कहा कि घाव के आसपास कोई कालापन या झुलसा नहीं है, लेकिन यह इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि बंदूक से गोली चलने से यह चोट नहीं पहुंचाई गई - डॉक्टर का मानना है कि मृतक की मौत बंदूक की गोली से हुई है।

आपराधिक अपील संख्या 1452 /2010 को खारिज करते हुए और आपराधिक अपील संख्या 1448 /2010 का निस्तारण हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1.1 आरोपी-अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 34 की सहायता से दोषी ठहराया गया है। पीडब्लू-2 के साक्ष्य में यह आया है कि आरोपी एम लाठी से लैस था और आरोपी वीएस बल्लम से लैस था और वे अन्य आरोपियों के साथ थे। जब साक्ष्यों की

संपूर्णता में जांच की गई, तो यह स्पष्ट रूप से पता चला कि आरोपी व्यक्ति शेड में मौजूद थे, उन्हें जाते हुए देखा गया और मृतक खून से लथपथ पाया गया। गवाहों ने विशेष रूप से आरोपी व्यक्तियों द्वारा ले जाए जा रहे हथियारों के बारे में बताया। यह प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष की कहानी बंदूक की गोली से लगी चोट पर टिकी है लेकिन लाठी या बल्लम से लगी चोट के संबंध में कोई सबूत नहीं है। यह बताना प्रासंगिक होगा कि घटनास्थल से कारतूस बरामद किए गए थे और पोस्टमार्टम करने वाले पीडब्लू-6 डॉक्टर ने बंदूक की गोली का घाव पाया था। घाव के आसपास कोई कालापन या झुलसा नहीं था। यह सच है कि डॉक्टर ने कहा कि घाव के आसपास कोई कालापन या झुलसा नहीं था, लेकिन इससे यह नहीं माना जा सकता कि चोट बंदूक की गोली से नहीं लगी थी। उन्होंने बताया कि मृतक की मौत गोली लगने से हुई है। [पैरा 13] [120-एफ-जी; 121-ए]

1.2 अपराध सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है या नहीं, यह रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री और उचित परिप्रेक्ष्य में उसकी सराहना पर निर्भर करेगा। दो मामलों के तथ्यों को एक जैसा नहीं माना जा सकता। अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई परिस्थितियों से सामान्य इरादे का पता लगाया जा सकता है। सामान्य इरादे की कल्पना तुरंत या अपराध के वक्त की जा सकती है। इस प्रकार, आईपीसी की धारा 34 की प्रयोज्यता तथ्य का प्रश्न है और इसे रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य से सुनिश्चित किया जाना है। किसी विशेष परिणाम को लाने का सामान्य इरादा मामले के तथ्य और स्थिति की परिस्थितियों के संदर्भ में कई व्यक्तियों के बीच मौके पर ही विकसित हो सकता है। क्या एक सिद्ध स्थिति में सभी संबंधित व्यक्तियों ने केवल एक साथ और स्वतंत्र इरादे विकसित किए हैं या क्या किसी विशेष परिणाम को लाने के लिए उनके दिमाग की एक साथ सर्वसम्मति विकसित की गई है और इस प्रकार उन सभी द्वारा

इरादा किया गया है, यह एक प्रश्न है जिस पर तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। पैरा 24] [125-डी-एफ]

1.3 लाठी से हुई किसी भी चोट की अनुपस्थिति आईपीसी की धारा 34 को खारिज करने का शासी कारक नहीं हो सकती। साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त-अपीलकर्ता अन्य अभियुक्तों के साथ आए थे जो बंदूक से लैस थे और वे स्वयं क्रमशः लाठी और बल्लम लेकर आए थे। वे हथियार लेकर गये, किसी विशेष स्थान पर पहुंचना और उसी समय शेड में प्रवेश करना और मृतक की हत्या करना निश्चित रूप से आईपीसी की धारा 34 के तहत रचनात्मक दायित्व को आकर्षित करता है। [पैरा 25] [126-बी)

1.4 यह दलील कि सभी चश्मदीद गवाह मृतक बीपी से संबंधित हैं और वे इच्छुक गवाह हैं, उनके संस्करण की सावधानीपूर्वक, सावधानी और समझदारी के साथ जांच की आवश्यकता है और जब उनके साक्ष्य को उक्त मापदंडों के साथ स्कैन किया जाता है, तो यह उक्त परीक्षण का सामना नहीं करता है जिसके लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मामला खराब हो जाता है और उचित संदेह से परे का सिद्धांत बिखर जाता है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि पीडब्लू-1 से 3 ने पक्षों के बीच पिछली दुश्मनी, मौके पर उनकी उपस्थिति, आरोपी व्यक्तियों के द्वारा ले जाये गये हथियारों, शेड से उनकी निकटता और सभी चार आरोपियों की पहचान स्थापित होने, के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने मृतक के खून से लथपथ पड़े होने के संबंध में भी गवाही दी है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि वे वास्तविक अपराधी को छोड़कर अपीलकर्ताओं को अपने रिश्ते की हत्या के लिए फंसाएंगे। इसके अलावा, जिरह में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जिसके लिए उनकी गवाही को बदनाम किया जा सके। [पैरा 26] [126-सी-ई)

1.5 इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि पीडब्लू-3 पीडब्लू-2 के साथ नहीं जा सकता था जब टयूबवैल के पास शेड में जा रहा था। जिरह में जो बात सामने आई है वह यह है कि वह रोजाना ट्यूबवेल पर नहीं जाता था।

न्यायालय ग्रामीण परिवेश से अनभिज्ञ नहीं रह सकता। कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह प्रतिदिन नहीं जा रहा था और उसकी गवाही कि वह उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पीडब्लू-2 के साथ गया था, को खारिज कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, उनका साक्ष्य न तो संदिग्ध है और न ही मन में कोई संदेह पैदा करता है। इस प्रकार, असली परीक्षा यह है कि पीडब्ल्यू 1 से 3 की गवाही आंतरिक रूप से विश्वसनीय है या नहीं। उसकी जांच की जाती है और यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वे सावधानीपूर्वक जांच और सतर्क दृष्टिकोण की कसौटी पर खरे उतरते हैं। उन पर भरोसा किया जा सकता है. [पैरा 28,29] [127-जी-एच; 128-ए-बी]

1.6 विचारण न्यायालय और उच्चन्यायालय के फैसले से यह ध्यान देने योग्य है कि पीडब्लू 1 से 3 की गवाही पर भरोसा किया गया है और उनके संस्करण को स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 को स्वाभाविक गवाह माना है जिन्होंने गवाही दी है कि आरोपी व्यक्ति अपराध करने के बाद जगह छोड़ रहे थे और उन्होंने उन्हें काफी करीब से देखा था। यह दलील कि वे इच्छुक गवाह थे और उनका निहितार्थ अभियुक्त व्यक्तियों के प्रति शत्रुतापूर्ण स्वभाव के कारण है, स्वीकार नहीं किया गया है। साक्ष्यों में यह बात सामने आई है कि गवाह और आरोपी एक ही गांव के हैं। इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि एनएस और पीडब्लू-2 द्वारा संदर्भित अन्य दो व्यक्तियों से पूछताछ न करने से अभियोजन पक्ष के संस्करण पर असर पड़ता है या अदालत के मन में कोई संदेह पैदा होता है। ऐसा निष्कर्ष इसलिए निकाला जाता है क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए गवाह भरोसेमंद हैं और अदालत उनकी गवाही पर सुरक्षित रूप से कार्रवाई कर सकती है। अभियोजन पक्ष के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का कोई औचित्य नहीं है। (पैरा 30, 32] [128-सी-ई; 129- जी; 130-ए)

1.7 यदि कोई व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं है, तो सामान्य इरादे का सवाल ही नहीं उठता। यदि सामान्य इरादा स्थापित हो जाए तो आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है।

अपीलकर्ता एमएस अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ गया था, जिनके पास पिस्तौल और बल्लम थे। वह स्वयं लाठी लेकर चल रहे थे और अपीलकर्ता वीएस बल्लम लेकर अन्य लोगों के साथ थे। उनका इरादा उस शेड में जाने का था जहां बिजली की रोशनी होने के कारण मृतक पढ़ाई कर रहा था। सामान्य इरादे को तथ्यों और परिस्थितियों से इकट्ठा किया जा सकता है और वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। [पैरा 34] [130-एफ-एच]

1.9 अपीलकर्ता-वीएस के लिए एक रिपोर्ट मांगी गई थी और अपराध की तारीख पर उसे 16 साल 3 महीने 10 दिन का किशोर पाया गया है। उक्त रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी गई है और राज्य ने निष्पक्ष रूप से कहा है कि अपराध की तारीख पर वह किशोर था। न्यायालय ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 7-ए और 2000 अधिनियम की धारा 20 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 में पेश किए गए संशोधनों पर भरोसा करते हुए मामले को खारिज कर दिया। यह मामला किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष इस टिप्पणी के साथ रखा गया है कि यदि किसी किशोर को विशेष गृह में रखे जाने की अधिकतम अवधि से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया है, तो बोर्ड उसे तुरंत हिरासत से रिहा कर देगा। चूंकि अपीलकर्ता-वीएस उस अधिकतम अवधि से अधिक समय तक हिरासत में रहा, जिसके लिए उसे एक विशेष घर तक सीमित रखा जा सकता था, सजा बरकरार रखते हुए, उसे हिरासत से रिहा कर दिया गया है। [पैरा 36] [131-बी-ई)

पांडुरंग और अन्य बनाम हैदराबाद राज्य एआईआर 1955 एससी 216: [1955] एससीआर 1083- भरोसा व्यक्त किया ।

प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य [2005] 1 एससीआर 1019: हरि राम बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (2009) 13 एससीसी 211: [2009] 7 एससीआर 623; सुरेश सखाराम नांगारे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2012) 9 एससीसी 249: [2012]

7 एससीआर 1186; जय भगवान और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (1999) 3 एससीसी 102; बिजेंद्र भगत बनाम उत्तराखंड राज्य (2015) 13 एससीसी 99; मोहन सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1963 एससी 174: [1962] पूरक एससीआर 848; हर्षदसिंह पकेलवनसिंह ठाकोर बनाम गुजरात राज्य (1976) 4 एससीसी 640: [1977] 1 एससीआर 626; जितेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2013) 11 एससीसी 193; लल्लन राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (2003) 1 एससीसी 268: [2002] 4 पूरक एससीआर 188; गौडप्पा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (2013) 3 एससीसी 67512013] 4 एससीआर 547; यूपी का किरपाल और भोपाल राज्य एआईआर 1954 एससी 706; भरवाड मेपा दाना और अन्य बनाम बॉम्बे राज्य एआईआर 1960 एससी 289: [1960] एससीआर 172; हुरी ओबुलु रेड्डी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1981) 3 एससीसी 675 कार्तिक मल्हार बनाम बिहार राज्य (1996) 1 एससीसी 614 [1995] 5 पूरक एससीआर 239: राणा प्रताप और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (1983) 3 एससीसी 327; हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम जियान चंद (2001) 6 एससीसी 71: ताखाजी हीराजी बनाम ठाकोर कुबेरसिंग चमनसिंग और अन्य (2001) 6 एससीसी 145; दहारी और अन्य। बनाम यूपी राज्य (2012) 10 एससीसी 256: 12012] 8 एससीआर 1219; मंजी सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2013) 12 एससीसी 746 [2013] 11 एससीआर 107; जोगिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2014) 11 एससीसी 335: [2013] 11 एससीआर 446- संदर्भित किया गया।

प्रकरण कानून संदर्भ

[2005] 1 एससीआर 1019	संदर्भित किया गया	पैरा 7
[2009] 7 एससीआर 623	संदर्भित किया गया	पैरा 7

[2012] 7 एससीआर 1186 संदर्भित किया गया पैरा 7

(1999) 3 एससीसी 102 संदर्भित किया गया पैरा 7

(2015) 13 एससीसी 99 संदर्भित किया गया पैरा 7

[1962] पूरक एससीआर 848 संदर्भित किया गया पैरा 8

[1977] 1 एससीआर 626 संदर्भित किया गया पैरा 8

(2013) 11 एससीसी 193 संदर्भित किया गया पैरा 8

[1955] एससीआर 1083 भरोसा व्यक्त किया पैरा 18

[2002] 4 पूरक एससीआर 188 संदर्भित किया गया पैरा 22

[2013] 4 एससीआर 547 संदर्भित किया गया पैरा 23

एआईआर 1954 एससी 706 संदर्भित किया गया पैरा 24

[1960] एससीआर 172 संदर्भित किया गया पैरा 24

(1981) 3 एससीसी 675 संदर्भित किया गया पैरा 26

[1995] 5 पूरक एससीआर 239 संदर्भित किया गया पैरा 26

(1983) 3 एससीसी 327 संदर्भित किया गया पैरा 27

(2001) 6 एससीसी 71 संदर्भित किया गया पैरा 30

(2001) 6 एससीसी 145 संदर्भित किया गया पैरा 31

[2012] 8 एससीआर 1219 संदर्भित किया गया पैरा 31

[2013] 11 एससीआर 107 संदर्भित किया गया पैरा 31

[2013] 11 एससीआर 446 संदर्भित किया गया पैरा 31

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील नंबर संख्या 1448/2010.

आपराधिक अपील संख्या 1019 /1981 में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय और आदेश दिनांक 13.05.2009 से।

मय

आपराधिक अपील नंबर 1452/2010

मुकेश के. गिरि, अधिवक्ता, अपीलकर्ता के लिए।

आर.के. दाश, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री अर्चना सिंह, अभीष्ठ कुमार, अभिषेक चौधरी, अधिवक्तागण; प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय दीपक मिश्रा, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया। वर्तमान अपीलें, विशेष अनुमति द्वारा, आपराधिक अपील संख्या 1019 /1981 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश दिनांक 13.05.2009 की बचाव क्षमता पर सवाल उठाती हैं। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सत्र परीक्षण संख्या 308/1979 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, मेरठ द्वारा पारित फैसले और आदेश की पुष्टि की है, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को दो अन्य लोगों के साथ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 सपठित 34 के तहत दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

2. अनावश्यक विवरणों को छानते हुए, वर्तमान अपीलों के निर्णय के लिए जिन तथ्यों को स्वीकार करना आवश्यक है, वे हैं कि एक तरफ आरोपी, धर्म पाल और उसके परिवार और दूसरी तरफ चरण सिंह, पीडब्लू-1, के बीच दुश्मनी थी। चरण सिंह, पीडब्लू-1, गजपाल, पीडब्लू-2, टेढ़ा, पीडब्लू-3 और नेपाल सिंह दस्तोई गांव के हैं। जिसमें मृतक

बदन पाल चरण सिंह का भतीजा भी है। जैसे कि आरोपी व्यक्ति संबंधित हैं। जैसा कि अभियोजन की कहानी आगे बढ़ती है, घटना से कुछ समय पहले, आरोपी धरम पाल के भाई गजे सिंह की हत्या कर दी गई थी और चरण सिंह, पीडब्लू-1, अन्य लोगों के साथ उसकी हत्या के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ा और अंततः बरी हो गए। बदन पाल की हत्या की घटना 26.03.1979 की शाम को हुई थी। बदन पाल एक छात्र था और वह ग्राम सर्वा के जंगल में स्थित अपने ट्यूबवेल पर, जिसका छप्पर बना हुआ था, रात्रि विश्राम करता था। घटना दिनांक को वह उक्त ट्यूबवेल पर था। गजपाल, पीडब्लू-2, और नेपाल सिंह उस मनहूस शाम को, बदन पाल के लिए भोजन ले जाते समय, रास्ते में टेढ़ा, पीडब्लू-3 से मिले, जो उपरोक्त ट्यूब-वेल से अपने खेतों की सिंचाई करना चाहता था। वे सभी शाम करीब 7.30 बजे ट्यूबवेल के पास पहुंचे । जब उन्होंने उक्त ट्यूबवेल के "कोठा" (शेड) के अंदर से बंदूक चलने की आवाज सुनी। वे बिना समय गंवाए वहां पहुंचे और देखा कि सभी चार आरोपी, धनी राम, धर्म पाल, महेंद्र और विजेंद्र, उस "कोठे" से बाहर आए थे। धनीराम और धर्मपाल के पास पिस्तौलें थीं, विजेंद्र के पास बल्लम था और महेंद्र के पास लाठी थी। उन्हें देखते ही वे अपने पैरों पर खड़े हो गये। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने बदन पाल को खून से लथपथ मृत पड़ा पाया। उक्त गवाहों ने ट्यूबवेल की छत पर लगे बिजली के बल्ब की रोशनी तथा टॉर्च की रोशनी में अभियुक्तों की पहचान की। घटना की एक रिपोर्ट चरण सिंह, पीडब्लू-1 की सहायता से देवेन्द्र सिंह द्वारा तैयार की गई और पुलिस स्टेशन खरखौदा में दर्ज की गई। आपराधिक कानून लागू होने के बाद, जांच एस.आई. राजवीर सिंह, पीडब्लू-8 द्वारा की गई, जिन्होंने अगले दिन सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच धारा 161 सीआरपीसी के तहत कुछ गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद पंचनामा तैयार किया। और घटनास्थल का नक्शा मौका और खून से सनी और बिना दाग वाली मिट्टी के साथ-साथ दो कारतूस भी एकत्र किए। इन्हें मौके पर ही सील कर दिया गया और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। 29.03.1979 को जांच एस.आई. वी.पी. सक्सेना को स्थानांतरित कर दी गई और उन्हें

11.04.1979 को पता चला कि धनी राम को छोड़कर सभी आरोपियों ने अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और उन्हें हिरासत में भेज दिया गया था। धनीराम को एस. आई. वी. पी. सक्सैना द्वारा दिनांक 19.04.1979 को मेरठ में गिरफ्तार किया गया। अंततः जांच पूरी होने के बाद आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया गया।

3. मामला सत्र न्यायालय में सौंपे जाने के बाद, 10.01.1980 को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के तहत आरोप तय किए गए। अभियुक्तों ने अपना अपराध त्याग दिया और मुकदमे का सामना करने का इरादा किया। आरोपों को सामने लाने के लिए अभियोजन पक्ष ने दो गवाहों से पूछताछ की और कुछ दस्तावेजों को प्रदर्शन के रूप में चिह्नित किया। बचाव पक्ष ने कोई सबूत पेश नहीं करने का फैसला किया।

4. विचारण न्यायलय ने रिकॉर्ड पर लाए गए नेत्र संबंधी और दस्तावेजी सबूतों का मूल्यांकन करते हुए आरोपी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 302 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 34 के तहत अपराध सी का दोषी पाया और उन्हें आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई।

5. सभी चार अभियुक्तों द्वारा दोषसिद्धि और सजा को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। आरोपियों में से एक धनी राम की उच्च न्यायालय के समक्ष अपील लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई और धनी राम की अपील स्थगित कर दी गई। जहां तक अन्य तीन आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् धर्म पाल, महेंद्र और विजेंद्र का संबंध है, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमति व्यक्त की और परिणामस्वरूप उनकी अपील खारिज कर दी। चाहे यह यहाँ कहा गया हो, जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कहा है, धर्मपाल की भी मृत्यु हो चुकी है। जो भी हो, उनके कहने पर कोई अपील नहीं है। वर्तमान दो अपीलें दो अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की

गई हैं जो उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश की पुष्टि से व्यथित हैं।

6. हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री मुकेश के. गिरि और यूपी राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर.के. डैश को सुना है।

7. दोषसिद्धि पर आपत्ति जताते हुए, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने कहा कि वर्तमान मामले में, सामान्य इरादे का अनुमान लगाने की कोई परिस्थिति नहीं है और चूंकि विचारों का कोई मेल नहीं हुआ है, इसलिए आईपीसी की धारा 34 की सहायता से दोषसिद्धि का समर्थन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि सजा पीडब्लू-1 से 3 की गवाही पर आधारित है, हालांकि एफआईआर के लेखक चरण सिंह, जो प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं; इसके अलावा, पीडब्लू-2, गजपाल का साक्ष्य प्रमुख विरोधाभासों, सुधारों और अलंकरणों से परिपूर्ण होने के कारण आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता है। यह आग्रह किया जाता है कि पीडब्लू-3 टेड्डा एक महत्वपूर्ण गवाह है क्योंकि पीडब्लू-1 ने खुद अपनी गवाही में स्वीकार किया है कि टेड्डा का ट्यूबवेल पर जाना नियमित नहीं था। श्री गिरि के अनुसार, अभियोजन पक्ष के सभी प्रमुख गवाहों, अर्थात् पीडब्लू-1 से 3 की गवाही विश्वसनीयता के योग्य नहीं है और वे विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं और इसलिए, उनके बयानों पर दोषसिद्धि की स्थापना नहीं की जा सकती है जो निश्चित रूप से निंदा से परे नहीं हैं। इस संबंध में वह आगे आग्रह करेंगे कि वे सभी एक-दूसरे से संबंधित हैं और इसलिए, उनकी गवाही की बेहद सावधानी से जांच की जानी चाहिए और जब ऐसी जांच की जाती है, तो वे बेदागता की स्थिति तक नहीं पहुंचते हैं और इसलिए, उस स्कोर पर अकेले, उनकी गवाही को खारिज करना होगा। विद्वान वकील का तर्क होगा कि नेपाल सिंह, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 के साथ आए थे, परीक्षित नहीं कराया गया है और राम लाल और कासा, जिनके बारे में कहा गया है कि वे ट्यूब-वेल पर पहुंचे थे पीडब्लू 2 की गवाही के अनुसार, को भी परीक्षित नहीं किया गया है और

वे स्वतंत्र गवाह हैं और उनकी गैर-परीक्षा अभियोजन पक्ष के संस्करण में एक असाध्य क्षति पैदा करती है। चिकित्सीय साक्ष्यों के अनुसार धनी राम और धरम पाल (दोनों मृतक) के हाथों में कथित तौर पर पिस्तौल से केवल एक गोली लगने की चोट बताई गई है और मृतक के शरीर पर लगी किसी भी चोट के लिए लाठी और बल्लम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, जो वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए थे और इसलिए, उन्हें अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। पीडब्लू-6 की गवाही का हवाला देते हुए डॉ. एम.सी. वार्ष्णेय के अनुसार, यह कहा गया है कि उक्त गवाह ने कहा है कि बंदूक की गोली के घाव पर कोई कालापन या झुलसा नहीं था और यह अभियोजन पक्ष के कथन को झुठलाता है कि मृतक की मृत्यु बंदूक की गोली की चोट से हुई थी। अंत में, यह प्रचारित किया गया कि विजेंद्र सिंह घटना की तारीख पर किशोर था और वह उस अवधि से अधिक समय तक हिरासत में रहा है जो एक किशोर के लिए बाल सुधार गृह में रहने के लिए आवश्यक है। अपनी दलीलों के समर्थन में, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य और अन्य, हरि राम और राजस्थान राज्य और अन्य, सुरेश सखाराम नांगारे बनाम महाराष्ट्र राज्य, जय भगवान और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और बिजेंद्र भगत बनाम उत्तराखंड राज्य; से प्रेरणा ली है।

8. विचारण कोर्ट के दोषसिद्धि के फैसले का समर्थन करते हुए, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन की मोहर लगी है, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दाश ने प्रस्तुत किया कि आरोपी महेंद्र सिंह को सही तरीके से दोषी ठहराया गया है और धारा 34 आईपीसी की सहायता से सजा सुनाई गई है। इस संबंध में उन्होंने मोहन सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और हर्षदसिंह पहलवानसिंह ठाकोर बनाम गुजरात राज्य पर भरोसा जताया है। श्री दाश ने आगे कहा कि वर्तमान मामले की पृष्ठभूमि में कुछ गवाहों से पूछताछ न करने से अभियोजन पक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा उद्धृत गवाहों ने स्पष्ट रूप से आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप स्थापित किया

है। जहां तक अपीलकर्ता द्वारा की गई अपील का संबंध है, विजेंद्र का सवाल है, विद्वान वरिष्ठ वकील ने किशोरता के दावे को काफी हद तक स्वीकार कर लिया और प्रस्तुत किया कि यह अदालत अपीलकर्ता पर जुर्माना लगा सकती है, जिसे जीतेन्द्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में दिये गये कानून के अनुसार मृतक के परिवार को मुआवजे के रूप में भुगतान किया जाएगा।

9. शुरुआत में, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मुख्य गवाह पीडब्लू-1 से पीडब्लू-3 और विचारण न्यायालय के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय ने भी उनके साक्ष्य को विश्वसनीयता प्रदान की है। पीडब्लू-1 एफआईआर के लेखक चरण सिंह ने गवाही दी है कि उन्होंने घटना की एफआईआर मौके पर ही तैयार कराई और फिर उसी रात हेड कांस्टेबल देवी राम, पीडब्लू-4 को सौंपकर थाना खरखौदा में दर्ज कराई, जिसने इसके बाद सामान्य डायरी में प्रविष्टि की। उन्होंने गवाही दी कि आरोपी धर्मपाल, महेंद्र और विजेंद्र सगे भाई हैं और वे उनके ही गांव के हैं; घटना की तारीख से लगभग नौ साल पहले, अभियुक्त धर्मपाल के सगे भाई गजे सिंह की हत्या कर दी गई थी, जिसके लिए उस पर और मृतक बदन पाल के सगे भाई हुकम सिंह और अन्य पर मुकदमा चलाया गया और अंततः उन्हे बरी कर दिया गया। उसने अपनी साक्ष्य में कहा है कि तभी से आरोपियों ने उससे दुश्मनी पाल ली। उनकी गवाही में यह भी सामने आया कि मृतक हाई स्कूल का छात्र था और अपनी पढ़ाई के लिए बिजली की रोशनी की सुविधा पाने के लिए ट्यूबवेल स्थित कोठा में रहता था। मृतक बदन पाल के चचेरे भाई गजपाल पीडब्लू-2 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपने चचेरे भाई नेपाल सिंह के साथ शाम करीब 7 बजे गांव से निकला था। उक्त ट्यूबवेल के कोठे के अंदर रहने वाले बदन पाल के लिए भोजन ले जा रहा था। उन्होंने आगे बताया कि टेढ़ा, पीडब्लू-3, उनके साथ थे और जब वे जगह पर पहुंचे, तो उन्होंने ट्यूबवेल के कोठे के अंदर से बंदूक चलने की आवाज सुनी। उसने गवाही दी है कि उसने सभी चार आरोपियों को ट्यूबवेल के उक्त कोठे के उत्तरी हिस्से से

बाहर आते देखा है और उसने आरोपियों धनी राम और धर्म पाल को पिस्तौल के साथ हत्या करते हुए और आरोपी महेंद्र और विजेंद्र को क्रमशः लाठी और बल्लम ले जाते हुए भी देखा है। उसने कोठे में जल रहे बिजली के बल्ब और उसके पास टॉर्च की रोशनी होने के कारण आरोपियों को पहचान लिया था। हालाँकि आरोपी व्यक्तियों को कोठे से बाहर आते हुए देखने के संबंध में उनसे बार-बार जिरह की गई है, लेकिन वास्तव में उनकी गवाही को महाभियोग योग्य बनाने के लिए कुछ भी नहीं मिला है। पीडब्लू-3, टेढ़ा ने भी आरोपी व्यक्ति की पहचान की है और पीडब्लू-2 की गवाही का समर्थन किया है। इसके अलावा, उक्त गवाह ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है और पीडब्लू-2 द्वारा बताए गए प्रत्येक आवश्यक विवरण की पुष्टि की है। विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 बेहद हितबद्ध गवाह हैं और इसके अलावा पीडब्लू-3 एक महतवपूर्ण गवाह था। विद्वान विचारण न्यायाधीश को उक्त विवाद में कोई तथ्य नहीं मिला, क्योंकि आरोपी व्यक्तियों की पहचान, उनके द्वारा ले जाए गए हथियारों और बरामदगी का स्पष्ट विवरण था। मालूम हो कि पिस्टल तो बरामद नहीं हुई, लेकिन घटना स्थल से दो कारतूस बरामद किये गये हैं। विद्वान ट्रायल जज इस राय पर पहुंचे कि अभियोजन पक्ष घटना स्थल पर गवाहों पीडब्लू 2 और 3 की उपस्थिति और मृतक की हत्या करने वाले आरोपी व्यक्तियों के संबंध में उनके संस्करण को साबित करने में सक्षम था। अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष यह आग्रह किया गया कि अभियुक्त की ओर से मृतक की हत्या करने का कोई मकसद नहीं था; कि विचारण न्यायालय ने पीडब्लू 2 और 3 के साक्ष्यों की जांच में सावधानी नहीं बरती है, जो अत्यधिक रुचि रखने वाले गवाह थे, कि पीडब्लू-2 की ओर से अपने साथ मशाल ले जाने का कोई औचित्य नहीं था और, किसी भी मामले में, उनकी यह गवाही कि उन्होंने अभियुक्त व्यक्तियों को देखा था, बिल्कुल अस्वीकार्य थी; मृतक को केवल एक आग्नेयास्त्र की चोट लगी थी और अपीलकर्ता लाठी और बल्लम से लैस थे और उन्होंने मृतक के

साथ मारपीट नहीं की थी और इसलिए, धारा 34 आईपीसी की सहायता से उन्हें दोषी ठहराने का विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से टिकाऊ था।

10. उच्च न्यायालय के फैसले की गहरी जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि उसने अपीलकर्ताओं की दलीलों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अभियोजन पक्ष के मामले को खत्म करने के लिए मामले की परिस्थिति में मकसद की कमी बहुत कमजोर थी; यह साक्ष्य में आया है कि आरोपी व्यक्तियों ने उस मामले में बरी होने के बाद उनके प्रति प्रतिशोध की भावना रखी थी, जहां उन पर आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध का मुकदमा चलाया गया था; ऐसा कोई कारण नहीं था कि गवाह जो मृतक के करीबी रिश्तेदार थे, असली दोषियों को छोड़कर आरोपियों को झूठा फंसाएंगे; पीडब्लू 2 और 3 की गवाही को केवल इस आधार पर खारिज करने का कोई कारण नहीं है कि वे संबंधित गवाह हैं। क्योंकि वे अपने संस्करण में अंतर्निहित हैं और उन्हें बदनाम करने में कोई असंगतता नहीं है; कि पीडब्लू-2 की ओर से अपने साथ मशाल ले जाना कोई असामान्य बात नहीं है; बिजली की रोशनी और टॉर्च की मदद से पीडब्लू 2 और 3 द्वारा आरोपी व्यक्तियों की पहचान की विद्वान ट्रायल जज ने सराहना की है और उक्त निष्कर्ष को खारिज करने का कोई कारण नहीं था; यह दलील कि पीडब्लू-3 एक आकस्मिक गवाह था और घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति संदिग्ध थी, वास्तव में स्वीकार्यता के लायक नहीं थी, क्योंकि उसकी गवाही विश्वसनीयता के योग्य थी, कि जिरह में गवाहों के साक्ष्य से कुछ भी ठोस नहीं निकाला जा सका। परीक्षण जिसके द्वारा संस्करण पर संदेह किया जा सकता है और इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष में कोई दुर्बलता या विकृति नहीं है; और यह कि विचारण न्यायालय ने आईपीसी की धारा 34 की सहायता से आरोपी व्यक्तियों को दोषी ठहराने में कोई गलती नहीं की है। इस संबंध में, उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि उक्त प्रावधान केवल साक्ष्य का नियम है और कोई ठोस अपराध नहीं बनाता है। इसने आगे कहा कि विचारण न्यायालय द्वाराचश्मदीद

गवाहों के साक्ष्य संतोषजनक, विश्वसनीय, सुसंगत और विश्वसनीय पाए गए हैं और जिरह में उनके सबूतों से ऐसा कुछ भी ठोस नहीं निकला जिससे उनके संस्करण में संदेह पैदा हो या उनकी गवाही को कमजोर या विकृत माना जा सके।

11. सुरेश सखाराम नांगारे (उपरोक्त) में आदेश का हवाला देते हुए अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में स्वीकार किया है कि सामान्य इरादे का प्रत्यक्ष प्रमाण शायद ही उपलब्ध है और वर्तमान मामले में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि ऐसे इरादे का अनुमान पूर्व-सम्मेलन के साक्ष्य के बिना लगाया जा सकता है। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि डॉ. वार्ष्णेय, पीडब्लू-6, जिन्होंने मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम किया था, के बयान के अनुसार, बंदूक की गोली के घाव पर कोई कालापन या कोई झुलसा हुआ निशान नहीं था, पूरे अभियोजन मामले की उत्पत्ति यह है कि हत्या ट्यूबवेल के कोठे पर हुई थी यानी बंदूक से करीब से गोली मारी गई थी त्यागने योग्य है।

12. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क होगा कि अपीलकर्ता महेंद्र की सजा टिकाऊ नहीं है क्योंकि मृतक के शरीर पर कोई भी चोट लाठी के कारण नहीं है जो कथित तौर पर महेंद्र के हाथ में थी। विद्वान वकील द्वारा बिजेंद्र भगत (उपरोक्त) के आदेश पर भरोसा जताया गया है, जिसमें इस अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि मृतक के शरीर पर लगी किसी भी चोट का कारण लाठी नहीं है, जो कथित तौर पर अपीलकर्ता के हाथ पर लगी थी।

13. जैसा कि सिद्ध है, आरोपी-अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 34 की सहायता से दोषी ठहराया गया है। पीडब्लू-2 के साक्ष्य में यह आया है कि अभियुक्त महेंद्र लाठी से लैस था और अभियुक्त विजेंद्र सिंह बल्लम से लैस था और वे अन्य अभियुक्तों के साथ थे। जब साक्ष्यों की संपूर्णता में जांच की गई, तो यह स्पष्ट रूप से पता चला कि आरोपी

व्यक्ति शेड में मौजूद थे, उन्हें जाते हुए देखा गया और मृतक खून से लथपथ पाया गया। गवाहों ने विशेष रूप से आरोपी व्यक्तियों द्वारा ले जाए जा रहे हथियारों के बारे में बताया। दलील यह है कि अभियोजन की कहानी बंदूक की गोली से लगी चोट पर टिकी है लेकिन लाठी या बैलैन से लगी चोट के संबंध में कोई सबूत नहीं है। यहां यह बताना प्रासंगिक होगा कि घटनास्थल से कारतूस बरामद कर लिए गए हैं और पीडब्लू-6 डॉक्टर, जिन्होंने पोस्टमॉर्टम का संचालन किया था, ने गर्दन के दाहिनी ओर हंसली के ठीक ऊपर और गर्दन के निचले हिस्से में 6 सेमी x 5 सेमी के क्षेत्र में प्रवेश आठ की बंदूक की गोली का घाव पाया था। घाव का आकार 1 सेमी x 0.15 सेमी से 0.5 सेमी x 0.5 सेमी x बोन डीप था। घाव के आसपास कोई कालापन या झुलसा नहीं था। यह सच है कि डॉक्टर ने कहा है कि घाव के आसपास कोई कालापन या झुलसा नहीं है, लेकिन इससे यह नहीं माना जा सकता कि चोट बंदूक की गोली से नहीं लगी है। उन्होंने बताया कि मृतक की मौत गोली लगने से हुई है।

14. मामले का मूल यह है कि क्या ऐसे मामले में आईपीसी की धारा 34 लागू होगी या नहीं। इस संबंध में, हम कुछ अधिकारियों का उल्लेख कर सकते हैं कि इस न्यायालय ने "सामान्य इरादे" की अवधारणा को कैसे देखा है और उसके बाद इस पर विचार करें कि यह मौजूदा मामले पर कैसे लागू होता है।

15. श्री गिरि ने जय भगवान (उपरोक्त) में प्राधिकार के पैराग्राफ 10 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

> "10. आईपीसी की धारा 34 को लागू करने के लिए इस तथ्य के अलावा कि दो या दो से अधिक आरोपी होने चाहिए, दो कारक स्थापित किए जाने चाहिए: (i) सामान्य इरादा और (ii) किसी अपराध के कमीशन में आरोपी की भागीदारी। यदि एक सामान्य इरादा साबित हो गया है लेकिन किसी भी प्रत्यक्ष कार्य के लिए व्यक्तिगत आरोपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, धारा 34 लागू होगी क्योंकि

अनिवार्य रूप से इसमें परोक्ष दायित्व शामिल है लेकिन यदि अपराध में आरोपी की भागीदारी साबित हो गई है और एक सामान्य इरादा अनुपस्थित है, तो धारा 34 लागू नहीं किया जा सकता है। हर मामले में, एक सामान्य इरादे का प्रत्यक्ष प्रमाण होना संभव नहीं है। इसका अनुमान कैश केस के तथ्यों और परिस्थितियों से लगाया जाना चाहिए।"

16. उन्होंने सुरेश सखाराम नांगारे (उपरोक्त) के फैसले पर भी भरोसा किया है। उक्त मामले में, न्यायालय ने आईपीसी की धारा 34 का उल्लेख करने के बाद राय दी कि उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 34 को लागू करने के लिए, इस तथ्य के अलावा कि दो या दो से अधिक आरोपी होने चाहिए, दो कारक स्थापित होने चाहिए: (i) सामान्य इरादा, और (ii) किसी अपराध में अभियुक्त की भागीदारी। यह आगे स्पष्ट करता है कि यदि सामान्य इरादा साबित हो गया है, लेकिन व्यक्तिगत आरोपी को कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं सौंपा गया है, तो धारा 34 लागू होगी क्योंकि अनिवार्य रूप से इसमें प्रतिवर्ती व्यवहार्यता शामिल है, लेकिन यदि अपराध में आरोपी की भागीदारी साबित हो गई है और सामान्य इरादा अनुपस्थित है, तो धारा 34 लागू नहीं की जा सकती।

17. उक्त मामले में, अदालत ने सबूतों का विश्लेषण करने के बाद राय दी कि अभियोजन पक्ष की ओर से यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अपीलकर्ता का मृतक को खत्म करने का कोई सामान्य इरादा था क्योंकि अपीलकर्ता के खिलाफ एकमात्र बात यह थी कि वह खुद को गांजा पीने के आरोपी के साथ जोड़ता था। इस तथ्यात्मक गणना पर, अदालत ने माना कि अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 34 की सहायता से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

18. इस संबंध में, हम पांडुरंग और अन्य बनाम हैदराबाद राज्य में प्राधिकारी के एक अंश को उपयोगी रूप से देख सकते हैं। उक्त मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने

आईपीसी की धारा 34 की प्रयोज्यता और दायरे पर विचार किया और उस संदर्भ में फैसला सुनाया कि: -

> "32.... इसके लिए एक पूर्व-व्यवस्थित योजना की आवश्यकता होती है क्योंकि इससे पहले कि किसी व्यक्ति को दूसरे के आपराधिक कृत्य के लिए परोक्ष रूप से दोषी ठहराया जा सके, यह कार्य उन सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए: महबूब शाह बनाम किंग एम्परर। तदनुसार, पहले से ही मन की बैठक होनी चाहिए। कई व्यक्ति एक साथ एक आदमी पर हमला कर सकते हैं और प्रत्येक का एक ही इरादा हो सकता है, अर्थात् मारने का इरादा, और प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से एक अलग घातक हमला कर सकता है और फिर भी किसी के पास धारा द्वारा आवश्यक सामान्य इरादा नहीं होगा क्योंकि पूर्व-व्यवस्थित योजना बनाने के लिए दिमागों की कोई पूर्व बैठक नहीं हुई थी। ऐसे मामले में, कैश ने जो भी चोट पहुंचाई उसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा, लेकिन किसी को भी किसी अन्य के कृत्य के लिए परोक्ष रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है; और यदि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि उसका अलग-अलग झटका घातक था, तो उसे हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता, चाहे उसका इरादा कितना भी स्पष्ट क्यों न हो। उसके अभियोग में हत्या को साबित किया जा सकता था: बुरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर" और महबूब शाह बनाम किंग एम्परर (उपरोक्त)। जैसा कि उनके आधिपत्य ने बाद के मामले में कहा है, "विभाजन जो उनकी सीमाओं को विभाजित करता है वह अक्सर बहुत पतला होता है: फिर भी, अंतर वास्तविक और पर्याप्त है, और अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो न्याय का गर्भपात हो जाएगा"।
>
> 33. योजना को विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है, न ही लंबे समय के अंतराल की आवश्यकता है। यह अचानक उत्पन्न हो सकता है और बन सकता है,

उदाहरण के लिए जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारने में मदद करने के लिए दर्शकों को बुलाता है और वे या तो अपने शब्दों या अपने कृत्यों से उसे अपनी सहमति दर्शाते हैं और हमले में उसके साथ शामिल होते हैं। तब मनों का आवश्यक मिलन होता है। यह एक पूर्व-निर्धारित योजना है, हालाँकि यह जल्दबाजी में बनाई गई और असभ्य तरीके से बनाई गई है। लेकिन पूर्व-व्यवस्था और पूर्व-निर्धारित संगीत कार्यक्रम होना चाहिए। जैसा कि बाद के प्रिवी काउंसिल मामले में हुआ, स्वतंत्र रूप से एक दूसरे का समान इरादा रखना पर्याप्त नहीं है जैसे कि अन्य को बचाने का इरादा, और यदि आवश्यक हो, तो विरोध करने वालों को मारने का इरादा।"

19. और, फिर से:-

"34.... लेकिन यह कहना परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में सामान्य नियम को दोहराने से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इस वर्ग के मामले के लिए साक्ष्य का कोई विशेष नियम नहीं है। कुल मिलाकर, यह हर मामले में तथ्य का प्रश्न है और परिस्थितियाँ कितनी भी समान क्यों न हों, एक मामले के तथ्यों को दूसरे मामले के तथ्यों पर निष्कर्ष निर्धारित करने के लिए एक मिसाल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जो कुछ आवश्यक है वह या तो पूर्व संगीत कार्यक्रम का प्रत्यक्ष प्रमाण होना है, या उन परिस्थितियों का प्रमाण है जो आवश्यक रूप से उस निष्कर्ष तक ले जाती हैं, या, जैसा कि हम इसे समय-सम्मानित तरीके से रखना पसंद करते हैं, "अपराधी तथ्य आरोपी की बेगुनाही के साथ असंगत होने चाहिए और किसी अन्य उचित परिकल्पना पर स्पष्टीकरण देने में असमर्थ होने चाहिए"। (सरकार के साक्ष्य, 8 वां संस्करण, पृष्ठ 30))।"

20. इस संदर्भ में, हम लाभ के साथ मोहन सिंह (उपरोक्त) मामले में संविधान पीठ द्वारा प्रतिपादित कानून के कथन का संदर्भ ले सकते हैं। उक्त मामले में, संविधान

पीठ ने माना है कि धारा 34 जो रचनात्मक आपराधिक दायित्व के मामलों से संबंधित है, यह प्रावधान करती है कि यदि कोई आपराधिक कार्य सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उत्तरदायी है। उसी तरह जैसे यह सब उसने अकेले ही किया हो। आगे यह देखा गया है कि धारा 34 द्वारा निर्धारित प्रतिवर्ती आपराधिक दायित्व का आवश्यक घटक सामान्य इरादे का अस्तित्व है। प्रश्न में सामान्य इरादा आरोपी व्यक्तियों को उत्तेजित करता है और यदि उक्त सामान्य इरादा आरोपित आपराधिक अपराध को अंजाम देने की ओर ले जाता है, तो सामान्य इरादे को साझा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनमें से किसी एक द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य के लिए रचनात्मक रूप से उत्तरदायी है। आईपीसी की धारा 149 और 34 के तहत रचनात्मक आपराधिक दायित्व की अवधारणा से निपटने वाली बड़ी पीठ ने व्यक्त किया कि जिस तरह एक ही सामान्य वस्तु को साझा करने वाले व्यक्तियों का संयोजन एक गैरकानूनी विधानसभा की विशेषताओं में से एक है, उसी तरह संयोजन का अस्तित्व भी समान इरादे साझा करने वाले व्यक्तियों की संख्या धारा 34 की विशेषताओं में से एक है। कुछ मायनों में दोनों धाराएं समान हैं और कुछ मामलों में वे ओवरलैप हो सकती हैं। सामान्य इरादा जो धारा 34 का आधार है, वह सामान्य उद्देश्य से भिन्न है जो एक गैरकानूनी सभा की संरचना का आधार है। सामान्य इरादा क्रिया-सम्मिलित को दर्शाता है और आवश्यक रूप से एक पूर्व-निर्धारित योजना के अस्तित्व को दर्शाता है और इसका मतलब दिमागों की पूर्व बैठक होना चाहिए। इस पर गौर किया जाएगा कि जिन मामलों में धारा 34 लागू की जा सकती है, वे सभी आरोपी व्यक्तियों की ओर से कार्रवाई में भागीदारी के तत्व का खुलासा करते हैं। कृत्य भिन्न हो सकते हैं; उनके चरित्र में भिन्नता हो सकती है, लेकिन वे सभी एक ही सामान्य इरादे से क्रियान्वित होते हैं। इसके बाद, न्यायालय ने कहा:-

"अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि धारा 34 द्वारा अपेक्षित सामान्य इरादा एक ही इरादे या समान इरादे से अलग है। जैसा कि प्रिवी काउंसिल ने महबूब शाह बनाम राजा-सम्राट (उपरोक्त) के अर्थ में सामान्य इरादे में देखा है। धारा 34 एक पूर्व-निर्धारित योजना का तात्पर्य है, और धारा को लागू करने वाले अपराध के आरोपी को दोषी ठहराने के लिए यह साबित किया जाना चाहिए कि आपराधिक कृत्य पूर्व-निर्धारित योजना के अनुसार मिलकर किया गया था और सामान्य इरादे के निष्कर्ष पर कभी नहीं पहुंचना चाहिए जब तक कि यह मामले की परिस्थितियों से निकाला जाने वाला एक आवश्यक निष्कर्ष न हो।"

21. हर्षदसिंह पहलवानसिंह ठाकोर (उपरोक्त) मामले में, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने आईपीसी की धारा 34 के तहत रचनात्मक दायित्व से निपटते हुए इस प्रकार फैसला सुनाया है: -

"रचनात्मक दायित्व तय करने वाली आईपीसी की धारा 34 निष्कासन की ऐसी परिष्कृत दलील को निर्णायक रूप से शांत कर देती है। (अमीर हुसैन बनाम यूपी राज्य; मैना सिंह बनाम राजस्थान राज्य देखें।") रचनात्मक आपराधिक दायित्व के लिए लॉर्ड सुमनेर का क्लासिक कानूनी शॉर्टहैंड, मिल्टनिक श्लोक में व्यक्त किया गया है "वे भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं" एक फोर्टियोरी तुरंत गठित सामान्य इरादे के मामलों को गले लगाता है, जिससे व्यक्तियों की बहुलता आपराधिकता में साहसिक कार्य में शामिल हो जाती है, कुछ मारते हैं, कुछ गायब हो जाते हैं, कुछ शत्रुतापूर्ण सिर विभाजित करते हैं, कुछ खून की बूंदें बहाते हैं। अपराध-बोध भागीदारीपूर्ण उपस्थिति या संचालन के साथ-साथ इरादे के समुदाय के साथ जुड़ा होता है। दंड संहिता के स्पष्ट दंडात्मक उद्देश्य को निरस्त करने या ख़त्म करने के लिए किसी भी बेहतर न्यायिक बारीकियों को लागू नहीं किया जा सकता है।"

22. लल्लन राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य' में न्यायालय ने बरेंद्र कुमार घोष (उपरोक्त) में निर्धारित सिद्धांत पर भरोसा करते हुए फैसला सुनाया है कि धारा 34 का सार एक विशेष परिणाम लाने के लिए आपराधिक कार्रवाई में भाग लेने वाले व्यक्तियों के दिमाग की एक साथ सहमति है।

23. गौड़प्पा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य में न्यायालय ने इस सिद्धांत को दोहराया है कि आईपीसी की धारा 34 एक आपराधिक कार्य करने में संयुक्त दायित्व का सिद्धांत बताती है और उस दायित्व का सार सामान्य इरादा के अस्तित्व में पाया जाना है। न्यायालय ने सवाल उठाया कि आम इरादे को कैसे इकट्ठा किया जाए और उसी का उत्तर देते हुए कहा कि आम इरादे को अपराध करने के तरीके, घटना के तुरंत पहले और बाद में आरोपी के आचरण, दृढ़ संकल्प और चिंता से इकट्ठा किया जाता है। कौन सा अपराध किया गया था, अभियुक्तों द्वारा उठाए गए हथियार और उनमें से एक या कुछ के कारण हुई चोट की प्रकृति और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि क्या अभियुक्तों का अपराध करने का सामान्य इरादा था जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया जा सकता था, परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

24. उपरोक्त अधिकारी यह बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक मामले को अपने तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। अपराध सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है या नहीं, यह रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री और उचित परिप्रेक्ष्य में उसकी सराहना पर निर्भर करेगा। दो मामलों के तथ्यों को एक जैसा नहीं माना जा सकता। अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई परिस्थितियों से सामान्य इरादे का पता लगाया जा सकता है। सामान्य इरादे की कल्पना तुरंत या अपराध के समय की जा सकती है। इस प्रकार, आईपीसी की धारा 34 की प्रयोज्यता तथ्य का प्रश्न है और इसे रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य से सुनिश्चित किया जाना है। किसी विशेष परिणाम को लाने का सामान्य इरादा मामले के तथ्य और स्थिति की परिस्थितियों के संदर्भ में कई व्यक्तियों के बीच मौके

पर ही विकसित हो सकता है। क्या एक सिद्ध स्थिति में उससे संबंधित सभी व्यक्तियों ने केवल एक साथ और स्वतंत्र इरादे विकसित किए हैं या क्या किसी विशेष परिणाम को लाने के लिए उनके दिमाग की एक साथ सर्वसम्मति विकसित की गई है और इस प्रकार उन सभी द्वारा इरादा किया गया है, यह एक प्रश्न है, तथ्यों पर निर्णय लेना होगा। (देखें: कृपाल और भोपाल बनाम यू.पी. राज्य)। भरवाड मेपा दाना और अन्य बनाम, बॉम्बे राज्य", में यह माना गया है कि धारा 34 आईपीसी का उद्देश्य एक ऐसे मामले को पूरा करना है जिसमें किसी पार्टी के व्यक्तिगत सदस्यों के कृत्यों को अलग करना मुश्किल हो सकता है जो सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने या आगे बढ़ाने में कार्य करते हैं। साबित करें कि उनमें से प्रत्येक ने वास्तव में क्या हिस्सा लिया था। यह धारा जिस सिद्धांत को अपनाती है वह अपराध करने के सामान्य इरादे से किसी कार्रवाई में भाग लेना है; एक बार ऐसी भागीदारी स्थापित हो जाने पर, धारा 34 तुरंत लागू हो जाती है।

25. मौजूदा मामले में यह तर्क दिया गया है कि लाठी या बल्लम से कोई चोट नहीं आई है। लाठी से हुई किसी भी चोट की अनुपस्थिति आईपीसी की धारा 34 को खारिज करने का शासी कारक नहीं हो सकती है। साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त-अपीलकर्ता अन्य अभियुक्तों के साथ आए थे जो बंदूक से लैस थे और वे स्वयं क्रमशः लाठी और बल्लम लेकर आए थे। हथियार ले जाना, किसी विशेष स्थान पर पहुंचना और उसी समय शेड में प्रवेश करना और मृतक की हत्या करना निश्चित रूप से आईपीसी की धारा 34 के तहत रचनात्मक दायित्व को आकर्षित करता है।

26. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री गिरि ने अगली दलील दी कि सभी चश्मदीद गवाह मृतक बदन पाल से संबंधित हैं और वे इच्छुक गवाह हैं, उनके बयान की सावधानीपूर्वक, सावधानी और समझदारी से जांच की आवश्यकता है और जब उनके साक्ष्य को उक्त मापदंड के साथ स्कैन किया जाता है, यह उक्त परीक्षण पर खरा नहीं उतरता है जिसके लिए अभियोजन पक्ष द्वारा निर्धारित मामला कमजोर हो जाता है और

उचित संदेह से परे का सिद्धांत बिखर जाता है। जैसा कि हम समझते हैं, उपरोक्त कथन में टिकने के लिए कोई आधार नहीं है, क्योंकि पीडब्लू-1 से 3 ने पक्षों के बीच पिछली दुश्मनी, मौके पर उनकी उपस्थिति, आरोपी व्यक्तियों द्वारा ले जाए गए हथियारों के बारे में, शेड से उनकी निकटता और चारों आरोपियों की पहचान स्थापित करने के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने मृतक के खून से लथपथ पड़े होने के संबंध में भी गवाही दी है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि वे वास्तविक अपराधी को छोड़कर अपीलकर्ताओं को अपने रिश्ते की हत्या के लिए फंसाएंगे। इसके अलावा, जिरह में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जिसके लिए उनकी गवाही को बदनाम किया जा सके। इस संबंध में हरि ओबुला रेड्डी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य" के एक अंश का संदर्भ फलदायी होगा। उक्त मामले में, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया है कि इसे एक अपरिवर्तनीय नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि इच्छुक साक्ष्य कभी भी दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकते हैं जब तक कि स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा भौतिक विवरण में भौतिक सीमा तक इसकी पुष्टि नहीं की जाती है। यह आवश्यक है कि इच्छुक गवाहों के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए और सावधानी के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि ऐसी जांच पर, इच्छुक गवाही आंतरिक रूप से विश्वसनीय या स्वाभाविक रूप से संभावित पाई जाती है, यह अपने आप में, किसी विशेष मामले की परिस्थितियों में, उस पर दोषसिद्धि का आधार बनाने के लिए पर्याप्त हो सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि संबंधित गवाह और इच्छुक गवाह के बीच अंतर होता है। एक रिश्तेदार प्राकृतिक गवाह होता है। कार्तिक मल्हार बनाम बिहार राज्य में न्यायालय ने कहा है कि एक करीबी रिश्तेदार जो प्राकृतिक गवाह है, उसे इच्छुक गवाह नहीं माना जा सकता है, क्योंकि "रुचि" शब्द यह दर्शाता है कि गवाह को किसी भी तरह से आरोपी के साथ कुछ रुचि होनी चाहिए। दूसरा, किसी दुश्मनी या किसी अन्य कारण से दोषी ठहराया गया।

27. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गिरि ने भी हमें इस आधार पर पीडब्लू-3, टेडा की गवाही को खारिज करने के लिए प्रेरित किया है कि वह एक मौका गवाह है। उनके मुताबिक घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी संदिग्ध है और उनके सबूत भी संदेह से परे नहीं हैं। मौका गवाह के तर्क पर टिप्पणी करते हुए, राणा प्रताप और अन्य बनाम हरियाणा राज्य में दो-न्यायाधीशों की पीठ को यह देखने के लिए बाध्य किया गया:-

> "हम अभिव्यक्ति "संयोग गवाहों" को नहीं समझते हैं। हत्याएं गवाहों को पूर्व सूचना देकर, उनकी उपस्थिति का अनुरोध करके नहीं की जाती हैं। यदि हत्या एक आवास गृह में की जाती है, तो घर के निवासी स्वाभाविक गवाह होते हैं। यदि हत्या किसी वेश्यालय में की जाती है, वेश्याएं और प्रेमी प्राकृतिक गवाह हैं। यदि सड़क पर हत्या की जाती है, तो केवल राहगीर ही गवाह होंगे। उनके साक्ष्य को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है या संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है कि वे केवल "मौका गवाह" हैं। अभिव्यक्ति "मौका गवाह" है "यह उन देशों से लिया गया है जहां हर आदमी के घर को उसका महल माना जाता है और हर किसी के पास कहीं और या दूसरे आदमी के महल में अपनी उपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण होना चाहिए। यह उस देश में सबसे अनुपयुक्त अभिव्यक्ति है जहां के लोग कम औपचारिक और अधिक आकस्मिक हैं। रेहड़ी-पटरी वालों और रेहड़ी-पटरी वालों की साक्ष्य इस आधार पर त्यागना कि वे "संयोग के गवाह" हैं, यहां तक कि जहां सड़क पर हत्या की गई हो, अच्छी समझ को त्यागना और सबूतों के बारे में बहुत सतही दृष्टिकोण रखना है।

28. उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर परीक्षण करने पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि पीडब्लू-3, पीडब्लू-2 के साथ नहीं जा सकता था जब वह ट्यूब-वेल के पास शेड में जा रहा था। जिरह में जो बात सामने आई है वह यह है कि वह रोजाना ट्यूबवेल पर नहीं जाता था। हम ग्रामीण परिवेश से अनभिज्ञ

नहीं रह सकते। कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि वह प्रतिदिन नहीं जा रहा था और उसकी गवाही कि वह उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पीडब्लू-2 के साथ गया था, किनारे कर देनी चाहिये । हम आश्वस्त हैं कि उनके साक्ष्य न तो संदिग्ध हैं और न ही मन में कोई संदेह पैदा करते हैं।

29. इस प्रकार, असली परीक्षा यह है कि पीडब्लू 1 से 3 की गवाही आंतरिक रूप से विश्वसनीय है या नहीं। हमने पहले ही इसकी जांच कर ली है और हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वे सावधानीपूर्वक जांच और सतर्क दृष्टिकोण की कसौटी पर खरे उतरते हैं। उन पर भरोसा किया जा सकता है.

30. श्री गिरि के तर्क का अगला मुद्दा यह है कि चूंकि नेपाल सिंह जिनके बारे में कहा गया था कि वे पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 के साथ आए थे, उनसे पूछताछ नहीं की गई है और इसी तरह, राम कला और बंसा, जिनके बारे में कहा गया था कि वे पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 के साथ आए थे, से पूछताछ नहीं की गई है। पीडब्लू-2 की गवाही के अनुसार ट्यूबवेल की जांच नहीं की गई है, अभियोजन पक्ष के संस्करण को खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसने जानबूझकर स्वतंत्र सामग्री गवाहों का हवाला नहीं दिया है। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसले से यह ध्यान देने योग्य है कि पीडब्लू 1 से 3 की गवाही पर भरोसा किया गया है और उनके संस्करण को स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 को स्वाभाविक गवाह माना है जिन्होंने गवाही दी है कि आरोपी व्यक्ति अपराध करने के बाद जगह छोड़ रहे थे और उन्होंने उन्हें काफी करीब से देखा था। यह तर्क कि वे इच्छुक गवाह थे और उनका निहितार्थ अभियुक्त व्यक्तियों के प्रति शत्रुतापूर्ण स्वभाव के कारण है, स्वीकार नहीं किया गया है और हम उक्त निष्कर्ष से सहमत हैं। साक्ष्यों में यह बात सामने आई है कि गवाह और आरोपी एक ही गांव के हैं। श्री गिरि का कहना है कि नेपाल सिंह, रामलाल और कलसा से पूछताछ न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए काफी महत्वपूर्ण है और जैसा कि

उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उनकी गैर-परीक्षा अभियोजन पक्ष के संस्करण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है और संदेह की भावना पैदा करती है। श्री गिरि के अनुसार नेपाल सिंह प्रत्यक्ष गवाह हैं। इस संबंध में हम एच.पी. राज्य बनाम ज्ञान चंद में आदेश का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें यह माना गया है कि भौतिक गवाह की गैर-परीक्षा फिर से रिकॉर्ड पर उपलब्ध गवाही के महत्व को खारिज करने का गणितीय सूत्र नहीं है, चाहे वह कितनी भी स्वाभाविक, भरोसेमंद और ठोस क्यों न हो। अभियोजन पक्ष के खिलाफ लगाए गए एक महत्वपूर्ण गवाह को अदालत में रोके रखने के आरोप की कैश केस के तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में जांच की जानी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि क्या गवाह अदालत में जांच के लिए उपलब्ध हैं और अभी तक अभियोजन पक्ष द्वारा रोके गए हैं। इसके बाद कोर्ट ने आगे फैसला सुनाया कि यह कोर्ट का कर्तव्य है कि वह पहले रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूतों की विश्वसनीयता का आकलन करे और अगर कोर्ट को लगता है कि पेश किए गए सबूत भरोसा करने लायक हैं और स्वीकार किए जाने लायक हैं, तो उपलब्ध किसी भी अन्य गवाह को परीक्षित न किया जाना, जिसको भी परीक्षित किया जा सकता था, लेकिन उसको परीक्षित नहीं किया गया, अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित नहीं करता है।

31. तखाजी हीराजी बनाम ठाकोर कुबेरसिंग चमनसिंग और अन्य में, यह माना गया है कि यदि कोई महत्वपूर्ण गवाह, जो घटना की उत्पत्ति या अभियोजन मामले के एक अनिवार्य हिस्से को उजागर करेगा, अन्यथा उसे ठोस रूप से सामने नहीं लाया जाएगा, या जहां अभियोजन मामले में कोई कमी या कमजोरी है जिसे किसी गवाह की जांच करके पूरा किया जा सकता था और गवाह को परीक्षित करके अच्छा बनाया जा सकता था, जो उपलब्ध होने के बावजूद जांच नहीं की गई है, अभियोजन मामले को कमी से ग्रस्त माना जा सकता है और ऐसे महत्वपूर्ण गवाह को रोकना अदालत को यह कहकर अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य करेगा कि

यदि गवाह की जांच की गई होती तो यह अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता। दूसरी ओर, यदि पहले से ही भारी सबूत उपलब्ध हैं और अन्य गवाहों से पूछताछ केवल दोहराव होगी या पहले से पेश किए गए सबूतों की नकल, ऐसे अन्य गवाहों की गैर-परीक्षा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है। यदि पहले से ही जांचे गए गवाह विश्वसनीय हैं और उनके मुंह से आने वाली गवाही निर्विवाद है, तो अदालत अन्य गवाहों के परीक्षण के तथ्य से प्रभावित हुए बिना, उस पर सुरक्षित रूप से कार्रवाई कर सकती है। डाहर्ल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में भौतिक गवाह के परीक्षण न किये जाने के बारे में चर्चा करते हुए, न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि जब वह एकमात्र सक्षम गवाह नहीं था जो तथ्यात्मक स्थिति को सही ढंग से समझाने में पूरी तरह से सक्षम होता और अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से चिकित्सा साक्ष्य और पुष्ट होता है। अन्य विश्वसनीय गवाहों की गवाही से अभियोजन पक्ष के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। मंजीत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य और जोगिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य" में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया है।

32. उपरोक्त मापदंडों पर परीक्षण किए जाने पर, हम श्री गिरि की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि पीडब्लू-2 द्वारा संदर्भित नेपाल सिंह और अन्य दो व्यक्तियों की गैर-परीक्षा अभियोजन संस्करण को प्रभावित करती है या न्यायालय के मन में कोई संदेह पैदा करती है। हम ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए गवाह भरोसेमंद हैं और अदालत उनकी गवाही पर सुरक्षित रूप से कार्रवाई कर सकती है। मौजूदा मामले में अभियोजन के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है।

33. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री गिरि ने मृतक के शरीर पर लाठी से लगी चोट के अभाव पर जोर देते हुए आग्रह किया है कि अपीलकर्ता-महेंद्र सिंह को आईपीसी की धारा 34 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उस संबंध में, उन्होंने हमें बिजेंद्र

भगत (उपरोक्त) में आदेश की सराहना की है। विद्वान वकील ने उक्त निर्णय के पैराग्राफ चार से प्रेरणा ली है। उक्त पैराग्राफ का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

> "... प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये दोनों आरोपी देशी पिस्तौल से भी लैस थे। मृतक को लगी चोटों में कटे हुए घाव और एक बन्दूक की चोट है। हालाँकि, मृतक के शरीर पर किसी भी चोट का कारण लाठी से नहीं बताया जा सकता है जो कथित तौर पर अपीलकर्ता के हाथ में थी। निस्संदेह, संजय कुमार के शरीर पर तीन चोटें किसी कठोर और कुंद वस्तु से हो सकती हैं। लेकिन गवाहों की गवाही और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्रियों को देखने के बाद, अपीलकर्ता की उपस्थिति और उसकी घटना में भूमिका उसकी संलिप्तता स्पष्ट रूप से संदिग्ध प्रतीत होती है। इसलिए, हम अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देना उचित समझते हैं..."

34. उसी पर भरोसा करते हुए, श्री गिरि द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जब मृतक के शरीर पर कोई लाठी का वार नहीं हुआ है जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है, तो अपीलकर्ता-महेंद्र सिंह बरी किए जाने के पात्र हैं। जिस अंश की हमारे लिए सराहना की गई है, उसकी सही ढंग से सराहना की जानी चाहिए। उस मामले में, अदालत ने मृतक के शरीर पर लगी चोट का उल्लेख किया है और देखा है कि चोट कैसे लगी, लेकिन बरी करने का कारण यह है कि अपीलकर्ता की उपस्थिति और घटना में उसकी भागीदारी अदालत को संदिग्ध प्रतीत हुई। यदि कोई व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं है तो सामान्य इरादे का सवाल ही नहीं उठता, जैसा कि पांडुरंग (उपरोक्त) में माना गया है, यदि सामान्य इरादा स्थापित हो जाता है, तो एक आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है। हम अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ता-महेंद्र सिंह को सौंपी गई भूमिका पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। वह अन्य आरोपियों के साथ गया था, जिनके पास पिस्तौल और बल्लम थे। वह स्वयं लाठी लेकर चल रहा था। इसी तरह, आरोपी-अपीलकर्ता विजेंद्र सिंह बल्लम लेकर अन्य लोगों के साथ जा रहा था। उनका इरादा उस शेड में जाने का

था जहां बिजली की रोशनी होने के कारण मृतक पढ़ाई कर रहा था। सामान्य इरादे को तथ्यों और परिस्थितियों से इकट्ठा किया जा सकता है और मौजूदा मामले में, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और इसलिए, बिजेंद्र भगत (उपरोक्त) में निर्णय से अपीलकर्ता को कोई सहायता नहीं मिली।

35. उपरोक्त विश्लेषण के मद्देनजर, हमें महेंद्र सिंह द्वारा दायर आपराधिक अपील संख्या 1452/2010 में कोई योग्यता नहीं मिली और तदनुसार, इसे खारिज किया जाता है।

36. जहां तक अपीलकर्ता-विजेंद्र सिंह का सवाल है, एक रिपोर्ट मांगी गई थी और अपराध की तारीख पर उसे 16 साल 3 महीने 10 दिन का किशोर पाया गया है। उक्त रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी गई है और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दाश ने निष्पक्ष रूप से कहा है कि अपराध की तारीख पर वह किशोर था। श्री गिरि ने हमें हर्ल राम (उपरोक्त) में आदेश की सराहना की है। हमने पाया कि न्यायालय किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 7-ए और 2000 अधिनियम की धारा 20 में पेश किए गए संशोधनों पर भरोसा कर रहा है, जिसके तहत अधिनियम की धारा 20 में प्रावधान और स्पष्टीकरण में जोड़े गए थे और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007,इस मामले को किशोर न्याय बोर्ड को इस टिप्पणी के साथ भेज दिया कि यदि उसे उस अधिकतम अवधि से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया है जिसके लिए एक किशोर को विशेष घर तक सीमित रखा जा सकता है, बोर्ड उसे हिरासत में से तुरंत रिहा करेगा। मौजूदा मामले में, चूंकि अपीलकर्ता-विजेंद्र सिंह उस अधिकतम अवधि से अधिक समय तक हिरासत में रहा, जिसके लिए उसे एक विशेष घर तक सीमित रखा जा सकता था, सजा बरकरार रखते हुए, हम उसे तुरंत हिरासत से रिहा करते हैं।

37. परिणामस्वरूप, आपराधिक अपील संख्या 1452 //2010 को खारिज किया जाता है और आपराधिक अपील संख्या 1448 /2010 को अपीलकर्ता-विजेंद्र सिंह को किशोर मानने

और उस संबंध में निर्देश जारी करने के लिए निस्तारित कियाजाता है जैसा कि यहां पहले कहा गया है।

निधि जैन अपीलें निस्तारित की गई ।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।